सान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 75 | जौनपुर, मंगलवार, 05 नवम्बर 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

सोरेन सरकार ने पांच साल तक जनता के लिए कुछ नहीं किया - पीएम मोदी

भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में दो चुनावी सभाओं को संबोधित कर माहौल को भाजपामय कर दिया। प्रधानमंत्री की रैली से पहले राज्य में सत्तारुढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को तब एक और बड़ा झटका भी लगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहैत विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के प्रस्तावकों में से एक मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सिदो–कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की मौजूदगी में देवघर में पार्टी में शामिल हुए। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा और गढ़वा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ष्एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है तो वहीं दूसरी तरफ श्रडड, कांग्रेस, त्श्रक के झूठे वादे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया लेकिन अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई हैं तब उन्होंने महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई–नई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग नकल कर सकते हैं लेकिन भाजपा के पास जो नेक नीयत है वो नेक नीयत कहां से लाओगे। हम आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड में झामुमो नीत सरकार पर ''वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने'' का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया था और कहा था कि यदि राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह आदिवासियों की जमीन को अवैध प्रवासियों को हस्तांतरित होने से रोकने के लिए कड़ा कानून लाएगी। अमित शाह ने यह भी घोषणा की कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा और झारखंड में आदिवासी आबादी को प्रभावित किए बिना समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के धालभूमगढ़ में भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया था कि राज्य में आदिवासी आबादी घट रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार ''बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक'' मानती है। अमित शाह ने यह भी घोषणा की थी कि सत्ता में आने पर भाजपा 51 वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद करेगी और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी जिसका भुगतान 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

भाजपा के संकल्प पत्र में क्या है?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणापत्र– 'संकल्प पत्र'– जारी करते हुए घोषणा

की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। शाह ने रांची में कहा, ''हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। (राज्य में) झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) सरकार इस झूठ का प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता से आदिवासियों के अधिकार के अलावा उनकी संस्कृति प्रभावित होगी। यह पूरी तरह निराधार है, क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।'' उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनजातीय समुदाय के अधिकारों पर कोई असर न पड़े। उन्होंने कहा, ''यदि भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है तो वह 'सरना धर्म कोड' के मुद्दे पर विचार–विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। झारखंड में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हृदय विदारक – राष्ट्रपति मुर्मू

देहरादून, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि यह खबर हृदय विदारक है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आज एक निजी बस गहरी खाई में गिर गई जिससे इसमें सवार कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, 43 सीट वाली बस अल्मोड़ा के मारचूला इलाके में 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई जिसमें लगभग 60 लोग सवार थे। राष्ट्रपति ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''अल्मोड़ा, उत्तराखंड में एक सड़क दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं शोकसंतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

उपचुनाव में दो विचारधाराओं के बीच जंग, कांग्रेस दर्ज करेगी जीत – सचिन पायलट

राजस्थान, एजेसी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि राजस्थान में उपचुनाव दो विचारधाराओं के बीच है और उनकी पार्टी सभी सात सीट पर जीत दर्ज करेगी। पायलटस, दौसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, "हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। ये चुनाव किसी एक जाति या दूसरी जाति का नहीं बल्कि विचारधारा का चुनाव है। यह उपचुनाव इस बात का साबित करेगा कि कौन दौसा की बेहतर सेवा कर सकता है। उन्होंने बाद में संवाददाताओं से कहा, "यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने दस वर्ष में लोगों से जो विश्वासघात किया है उसे लोग देख रहे हैं। साल भर से उनकी सरकार ने यहां राजस्थान में हमारी (कांग्रेस) सरकार की सारी जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया।घोषणा पत्र में किये खुद के वादे वे (सत्तारूढ़ भाजपा) पूरे नहीं कर पा रहे हैं। पायलट ने कहा, "जनता जवाब मांगेगी। जनता को जवाब मांगने का अवसर चुनाव के माध्यम मिलता है। इस चुनाव में एक संदेश जाएगा और भारी मतों से हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सात सीट पर होने वाले उपचुनाव में हम अच्छा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मुझे विश्वास है।

बालू, पत्थर, खनिज, मनरेगा, आवास सबका पैसा खा गई जेएमएम - शिवराज सिंह चौहान

रांची, एजेसी। केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को खिजरी विधानसभा सीट के उम्मीदवार रामकुमार पाहन के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि 23 नवंबर को राज्य की मौजूदा सरकार की विदाई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जेएमएम–कांग्रेस गठबंधन की सरकार से जनता त्राहि–त्राहि कर रही है। इसने वन संपदा, जल संपदा और खनिज संपदा से भरपूर सुंदर राज्य को तबाह कर दिया है। इसके नेता बालू, पत्थर, खनिज, मनरेगा, आवास तक का पैसा खा गए। यहां नेताओं–मंत्रियों के घरों से लूट के पैसों के पहाड़ बरामद हो रहे हैं। अगर झारखंड को बचाना

है तो एक नई क्रांति करनी पड़ेगी। ये वो धरती है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ उलगुलान यानी क्रांति का बिगुल फूंका था। आज जेएमएम–कांग्रेस गठबंधन सरकार में भी शोषण की अति हो गई है और यहां फिर से उलगुलान की जरूरत है। चौहान ने कहा कि विदेशी घुसपैठिए यहां आ रहे हैं, बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर रहे हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, पंचायतों पर कब्जा कर रहे हैं। झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही इन विदेशी घुसपैठियों को चुन–चुनकर बाहर निकाला जाएगा। हेमंत सोरेन की सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए चौहान ने कहा कि पांच साल पहले हेमंत सोरेन ने महिलाओं से वादा किया था कि, उन्हें प्रति माह 2 हजार रुपए चूल्हा खर्च के लिए दिया जाएगा, लेकिन 4 साल 10 महीने बहनों की याद नहीं आई और चुनाव आते ही वोटों की लालच में बहनों के बैंक खाते में 1–1 हजार रुपए डाल दिए। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और महाराष्ट्र में बहनों के बैंक खाते में सम्मान राशि दे रहे हैं। झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनते ही बहनों के बैंक खाते में हर महीने की 11 तारीख को गोगो दीदी योजना के तहत 2,100 रुपए की राशि डाली जाएगी। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि झारखंड में बालू भी बाल्टियों में किलो से बेची जा रही है।

भाजपा ने वायनाड में भूस्खलन की घटना का राजनीतिकरण किया – प्रियंका गांधी

वायनाड, एजेसी। कांग्रेस महासचिव और वायनाड लोकसभा सीट से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाद्रा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस साल जुलाई में हुई भूस्खलन की घटना का राजनीतिकरण किया। चुनाव प्रचार के दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए उन्होंने सुल्तान बाथरी विधानसभा क्षेत्र के केनिचिरा में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ''जिस आपदा से लोगों को भारी पीड़ा हुई, उसका भी भाजपा ने राजनीतिकरण कर दिया...हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, जहां आपको अपने देश, अपनी जरूरतों और आप जिस तरह की राजनीति चाहते हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि पूरे देश में नफरत फैला रही भाजपा की राजनीति की पहचान क्रोध, विभाजन और बर्बादी है। उन्होंने कहा कि लोगों के समक्ष

खड़े वास्तविक मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उनकी समस्याएं अनसुलझी हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बेरोजगारी अब तक के उच्चतम स्तर पर है और कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिनके रुकने का कोई संकेत नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा, ''राजनीति इन मुद्दों को हल करने पर केंद्रित नहीं है। भाजपा की राजनीति का उद्देश्य पूरी तरह से आपका अपनी समस्याओं से ध्यान भटकाना है, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े।'' उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भूस्खलन से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आवश्यक सहायता राशि देने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा, ''यदि आप मुझे संसद में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके लिए किसी और की तुलना में मैं अधिक मेहनत कर सकती हूं।

अगर एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं होगा तो घुसपैठिए पूरे राज्य पर कर लेंगे कब्जा – हिमंत

झारखंड, एजेसी। असम के सीएम और झारखंड के बीजेपी सह–प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं होगा तो घुसपैठिए पूरे झारखंड पर कब्जा कर लेंगे। अपने बयान में हिमंता ने कहा कि हमें झारखंड में घुसपैठियों की पहचान के लिए एनआरसी और ऐसे सर्वे करने होंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम यूसीसी लाएंगे लेकिन आदिवासियों को इससे दूर रखेंगे। अगर एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं होगा तो घुसपैठिए पूरे झारखंड पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि घुसपैठिए आएं क्योंकि वे उनके वोट बैंक हैं। वहीं, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मंत्र पर चलते हुए विकास की बात कर रही है, देश और प्रेदश के निवासियों को जोड़ने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का एक ही मकसद है– पहले बांटो, उसके बाद जो घुसपैठिये घुस जाएं, वो काटें। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि घुसपैठियों को चुन–चुन कर बाहर करेंगे। दूसरी ओर, जेएमएम और कांग्रेस का मूल मंत्र है– घुसपैठियों का चुन–चुन कर ब्याह करेंगे। भाजपा नेता ने साफ तौर पर दावा किया कि कांग्रेस हो, जेएमएम हो या आरजेडी हो... ये सभी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। इनको घुसपैठियों से कोई परहेज नहीं है, ये घुसपैठियों को गले लगाते हैं... क्योंकि घुसपैठिये इनका वोटबैंक हैं।

एथलीटों के लिए पुरस्कारों के साथ खेल नीति को बढ़ावा देने की योजना, सीएम चंद्रबाबू नायडू सरकार की नई पहल

आंध्र प्रदेश, एजेसी। आंध्र प्रदेश पदक विजेताओं और ओलंपियनों के लिए नए प्रोत्साहनों के साथ राज्य में खेलों को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की खेल नीति को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का संकल्प लिया है। राज्य सचिवालय में एक समीक्षा बैठक के दौरान, उन्होंने एथलीटों को प्रेरित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया कि उन्हें वह मान्यता मिले जिसके वे हकदार हैं। ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार नकद पुरस्कारों में उल्लेखनीय वृद्धि करने की योजना बना रही है। स्वर्ण पदक विजेताओं को अब 75 लाख रुपये से बढ़कर 7 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि रजत पदक विजेताओं को 50 लाख रुपये के बजाय करोड़ रुपये मिलेंगे, और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रुपये से बढ़कर 3 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, ओलंपिक में भाग

लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 50 लाख रुपये का नकद प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एशियाई खेलों के एथलीटों के लिए पुरस्कार बढ़ाने की योजना की भी रूपरेखा तैयार की, जिसमें स्वर्ण पदक विजेताओं को 4 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। एशियाई खेलों में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को प्रोत्साहन के रूप में 10 लाख रुपये मिलेंगे। नायडू ने लोकप्रिय खेल लीगों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

दिल्ली की सीएम आतिशी ने आईटीओ पर लिया जायजा

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को छठ पूजा के लिए आईटीओ घाट पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और घोषणा की कि शहर भर में 1,000 से अधिक स्थलों पर छठ घाटों की तैयारी चल रही है। आतिशी ने कहा कि आज शहर में 1000 से अधिक स्थानों पर छठ घाट बनाए जा रहे हैं।

हमारे सभी मंत्री और विधायक छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं भाजपा से छठ पूजा पर राजनीति नहीं करने का आग्रह करती हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ का पर्व पूर्वांचली भाई–बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और हम पिछले 10 साल से इस पर्व को पूरी दिल्ली में धूमधाम से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले दिल्ली में सिर्फ 60 जगह पर सरकार द्वारा छठ पर्व मनाया जाता था लेकिन आज 1000 से ज्यादा शानदार छठ घाट दिल्ली सरकार ने तैयार किये हैं जहां सभी लोग अच्छी तरह छठी मैया की पूजा कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उधर चिराग दिल्ली में बीजेपी की DDA द्वारा छठ पूजा को रोकना बीजेपी की पूर्वांचल विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। विभिन्न भारतीय राज्यों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने वाला सूर्य–पूजा का त्योहार छठ पूजा इस साल 5 से 8 नवंबर तक मनाया जाएगा। संबंधित घटनाक्रम में, विधायक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा की आलोचना जारी रखी और उन पर राजधानी में विशिष्ट स्थलों पर भक्तों को पूजा करने से रोकने का आरोप लगाया।

हाथियों की अंतरराज्यीय विचरण पर छत्तीसगढ़ सरकार से चर्चा करेंगे – सीएम

भोपाल, एजेसी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वह छत्तीसगढ़ के अपने समकक्ष से को लेकर दोनों राज्यों के वन विभागों के बीच समन्वय की भी वकालत की। पिछले सप्ताह मध्यप्रदेश में

हाथियों के झुंड के पड़ोसी राज्य से उनके प्रदेश में प्रवेश करने से उत्पन्न चुनौतियों को लेकर चर्चा करेंगे। यादव का आज छत्तीसगढ़ जाने का कार्यक्रम है। उन्होंने विभिन्न मुद्दों उमरिया जिले के बांधवगढ़ बाघ संरक्षित क्षेत्र (बीटीआर) में 10 हाथियों की मौत हो गयी थी। यादव ने इन हाथियों की मौत की उच्च स्तरीय जांच के बाद रविवार को बीटीआर के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। पिछले सप्ताह उमरिया जिले में एक हाथी ने कुचलकर तीन लोगों को मार डाला था। यादव ने कहा, '' हाथियों से जुड़ी घटनाएं आमतौर पर छत्तीसगढ़ से हाथियों के झुंड के आने के कारण होती हैं। मैं इस मुद्दे को (छत्तीसगढ़ के) मुख्यमंत्री के समक्ष उठाऊंगा।'' उन्होंने कहा, '' दोनों राज्यों के वन विभागों को आपस में समन्वय कायम करना चाहिए ताकि हम एक–दूसरे के संपर्क में रह सकें और हाथियों के बड़े झुंडों के प्रवेश से उत्पन्न होने वाली स्थिति से बच सकें। हम भविष्य में आने वाली कठिन चुनौतियों के बारे में मिलकर चर्चा करेंगे।

बिहार सरकार की 'मेडल लाओ-नौकरी पाओ' योजना, अब तक 342 खिलाड़ियों को मिली नौकरी

पटना, एजेंसी। बिहार सरकार द्वारा 2010 में शुरू की गई मेडल लाओ–नौकरी पाओ' योजना के तहत अब तक 342 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2010 में ही घोषणा करते हुए कहा था कि खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी मेडल जीतें, सरकार उन्हें नौकरी देगी। इसके तहत वर्ष 2010 में 33 खिलाड़ियों, वर्ष 2011 में 125 खिलाड़ियों, वर्ष 2015 में 82 खिलाड़ियों तथा वर्ष 2020 में 31 खिलाड़ियों को यानी 271 खिलाड़ियों को लिपिक वर्ग की नौकरियां दी गई। इसके बाद राज्य में खेलों के प्रति युवाओं की रूचि बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा 'मेडल लाओ नौकरी पाओ' तर्ज पर 'बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023' बनाई गई। इसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं में

राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023–24 में मेडल लाओ–नौकरी पाओ योजना के तहत 71 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में प्रथम वर्ग श्रेणी की सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा गया। अब तक बिहार में 342 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे, तभी इन्होंने रेलवे में खिलाड़ियों को नौकरी देने की व्यवस्था की थी। देशभर के सैकड़ों खिलाड़ियों को रेलवे में नौकरी दी गई है। रेलवे में खिलाड़ियों को नौकरी देने की तर्ज पर ही वर्ष 2010 से बिहार में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाने लगी। बताया गया कि 'मेडल लाओ नौकरी पाओ' की तर्ज पर 'बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023' बनाई गई है। इसके तहत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में मेडल पाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दी जा रही है।

संपादकीय

स्वस्थ समाज का निर्माण

बचपन और जवानी की तरह बुढ़ापा भी मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। बुढ़ापा, जवानी और बचपन में बुनियादी अंतर यह है कि बचपन और जवानी जीवन में एक बार आती है और चली जाती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो आखिरी सांस तक हमारे साथ रहता है। आम तौर पर, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का चरम 60 वर्ष देखा हो, उसे पुराने क्लब के सदस्य के रूप में पहचाना जाता है। उम्र के इस पड़ाव पर समाज को समझदारी की उम्मीद होती है. उसे ज्येष्ठ की उपाधि देता है, परन्तु उस समयदुख तो तब होता है जब दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि कोई बूढ़ा आदमी आ रहा है, लेकिन जब मुंह खोलता है तो वह बूढ़ा आदमी निकलता है। बूढ़े आदमी और बूढ़े आदमी के बीच अंतर यह है कि बूढ़ा आदमी हमेशा समझदारी से बात करता है जबकि बूढ़ा सिर्फ बात करता है। आधुनिक समय में हर रिश्ते में दरारें आ रही हैं। माता–पिता अक्सर बुढ़ापे में खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। दुःख की बात है कि बच्चे अपने माता–पिता को बृहद–आश्रम में छोड़ने से भी नहीं हिचकिचाते। ऐसी सामाजिक घटना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि बेहद शर्मनाक है. तो इसे बंद कर दीजिएयह आवश्यक है क्योंकि बुजुर्गों की उपेक्षा करके हम स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते। यह समस्या दिन–ब–दिन विकराल क्यों होती जा रही है? हालाँकि नई पीढ़ी श्खाओ, पियो, राख करोश के सिद्धांत में गलत है, भौतिकवाद मूल्यों पर भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि बच्चे हमेशा गलत होते हैं। कई बार माता–पिता की भी गलती देखने को मिलती है। अधिकांश बुजुर्गों को उनके बचपन के दौरान उनके माता–पिता द्वारा अनुशासित किया जाता है और उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है। तो अब उनके अपने बच्चे भी हैंडांटना चाहते हैं, लेकिन ऊंचे पढ़े–लिखे बच्चे यकीनन बहुत बातें करते हैं। मशीनीकरण के युग में नई पीढ़ी को टोका–टोकी बर्दाश्त नहीं होती, जबकि पुरानी पीढ़ी उन पर अपना अनुभव और ज्ञान थोपना चाहती है। शादी के बाद जब माता–पिता अपनी बहू को सिर्फ एक स्थाई नौकरानी समझने लगते हैं तो समस्या यहीं से शुरू होती है। जिस लड़की ने मंगनी के दौरान बातचीत के दौरान अपने पिता को तड़पते देखा है. उनसे सच्चे सम्मान की उम्मीद करना भी मूर्खता है. इस स्थिति मेंक्रिया की प्रतिक्रिया होती है. प्रतिक्रिया, क्रिया के इस चक्र में रिश्तों पर असर पड़ने लगता है। जब आपके बेटे की शादी हो तो आपको अपनी बहू को अपनी बेटी मानना चाहिए क्योंकि शादी के समय वह अपना घर और माता–पिता छोड़कर आपके घर आती है। अब आप उसके माता–पिता हैं. यह आप पर निर्भर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। आप उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार करेंगे. यदि आप अच्छे संस्कारों के साथ व्यवहार करेंगे तो बदले में आपको सम्मान मिलेगा। ऐसी स्थिति जहां किसी को दबाव डालने के लिए मजबूर किया जाता हैउसके बाद यह उसी ताकत से टूट जाएगा या वापस उछल जाएगा। विज्ञान के इस सिद्धांत को हम नकार नहीं सकते। माता–पिता अक्सर शादी के बाद अपने बेटे के व्यवहार में बदलाव को लेकर शिकायत करते हैं। माता–पिता सोचते हैं कि उनका बेटा भोला है और नूह चतुर है। इस कारण वह पत्नी का गुलाम बन गया है। हालांकि, यह मामला हमेशा नहीं होता है। माता–पिता को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बेटा भी किसी का पति है। आजकल अगर पढ़े–लिखे लड़के अपनी पत्नियों के काम में मदद करते हैं तो उन्हें श्ताकत का गुलामश कहा जाता है।श्नहीं कहा जा सकता क्योंकि पत्नी कई ऐसे काम करती है जो पति के हिस्से के होते हैं। आपसी सहयोग से ही गृहस्थ जीवन का रथ आगे बढ़ सकता है। कई बुजुर्गों को जब नई बहू मिलती है तो उन्हें पहले आई बड़ी बहू में कई कमियां नजर आने लगती हैं। वे भूल जाते हैं कि अब तक उनकी सेवा किसने की है। नई सदस्य कभी–कभी परिवार में बसने के लिए बड़ों को नहीं टोकती, लेकिन एक साल बाद जब वह अपना रंग दिखाना शुरू करती है तो ऐसा लगता है कि अब वह ज्यादा बातें करने लगी है। घर आये अतिथियों का व्यवहार द्यकई बार जब बुजुर्ग आह भरते हुए कहता है, श्बस आओश तो मेहमान उसके लहजे से समझ जाता है कि वह अपना दुख बांटने को तैयार है। मौका मिलते ही बूढ़ा मेहमानों के सामने अपनी भावनाएं ड्रम से गेहूं की तरह उड़ेल देता है. फिर यह खास मेहमान सभी रिश्तेदारों के बीच मध्यस्थता करके बूढ़े और उसके बच्चों का श्दुखश बांटता है। अगले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार हो जाता है और घर का माहौल सामान्य हो जाता है, लेकिन सभी रिश्तेदारों के बीच बच्चों की छवि को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ईइसलिए अपने रिश्तेदारों के सामने अपने बच्चों की बुराई न करें बल्कि अपने बच्चों की उपलब्धियों का जिक्र करके गर्व महसूस करें, क्योंकि आपके बच्चे आपके लिए जो कर सकते हैं, वह रिश्तेदार नहीं कर सकते। दूसरों को बार–बार बेटा–बेटा कहकर पुकारना और अपने बेटों को हमेशा रोआब कहकर पुकारना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बुजुर्गों को छोटे बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए. उन्हें बाहर घुमाने ले जाएं. सेहत को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कभी–कभी खाना खिलाने ले जाएं. इस तरह आपका समय अच्छा बीतेगाऔर बच्चे आपसे अधिक प्यार करेंगे।

एआई कम्पेनियनशिप ऐप्स के दूसरे पहलू

आदित्य

फ्लोरिडा के एक बच्चे सेवेल सेटर III ने हाल ही में आत्महत्या कर ली। एक ऐसी घटना में जो चौंकाने वाली और चिंताजनक है, उसकी माँ ने Character-एआईके खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चौटबॉट्स के साथ गहन बातचीत करने देता है, उसके बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए। अतीत में, ऐसे ऐप्स पर कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया है। यह अब तेजी से बढ़ते, बड़े पैमाने पर अनियमित, एआई साथी ऐप्स के उद्योग का दूसरा पहलू है। इन ऐप्स के उपयोगकर्ता अपने स्वयं के एआई साथी बना सकते हैं और उनके साथ टेक्स्ट मैसेज, वॉयस चौट आदि पर चौट कर सकते हैं। इनमें से कई ऐप अंतरंग संबंधों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और कुछ तथाकथित अकेलेपन की महामारी से निपटने के तरीके के रूप में खुद को बाजार में पेश करते हैं। विडंबना यह है कि ऐसे कई अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि इस तरह की तकनीक ने अकेलेपन की महामारी को और बढ़ा दिया हैरू उदाहरण के लिए, मैसाचुसेट्स लोवेल विश्वविद्यालय में किए गए शोध में पाया गया कि तकनीक और सोशल मीडिया पर निर्भरता व्यक्तिगत संबंधों को खत्म कर देती है, जिससे लोग अकेले और अलग–थलग पड़ जाते हैं। इसका तकनीकी उद्योग के लिए कोई मतलब नहीं है, जिसने एक आकर्षक बाजार को महसूस किया है जो अकेलेपन की महामारी से लाभ कमा सकता है। तकनीकी उद्योग एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसने मानवीय कमजोरियों का

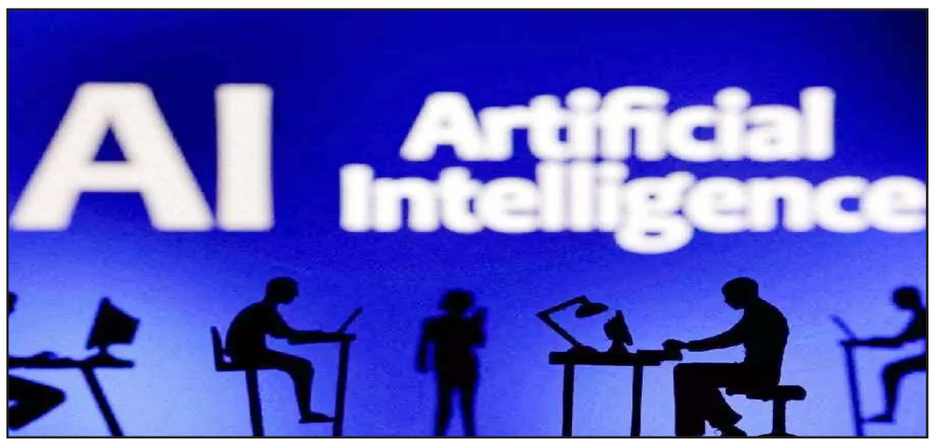

फायदा उठाकर पैसे कमाए हैं। घोटालेबाज अक्सर लोगों को ठगने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, खघस तौर पर उन लोगों को जो साथी की तलाश में होते हैं, उनकी जीवन भर की बचत हड़प लेते हैं। अमेरिकियों ने 2023 में ऑनलाइन रोमांस घोटालों में 13.23 करोड़ अपराधियों के हाथों अनुमानित +12.5 बिलियन खो दिए, जिसमें से +652 मिलियन अकेले लोगों को शिकार बनाने वाले रोमांस घोटालों में थे। यह घटना केवल पश्चिम तक सीमित नहीं हैय उसी वर्ष, भारतीयों ने ऑनलाइन रोमांस घोटालों में 13.23 करोड़ रुपये खो दिए। बेशक, तकनीक में सुरक्षा कवच स्थापित करने की जरूरत है। पॉप–अप में कोडिंग जो उपयोगकर्ताओं को आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन पर ले जाती है या कुछ कीवर्ड के इस्तेमाल पर पर्यवेक्षकों, माता–पिता या अधिकारियों को अलर्ट भेजती है, एक तरीका हो सकता है। लेकिन समस्या की जड़ लोगों में है – युवा और बुजुर्ग ज्यादा असुरक्षित हैं – अंतरंगता और सलाह के लिए तकनीक की ओर रुख कर रहे हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि निष्पक्षता और गैर–निर्णयात्मक समझ ही वे कारण हैं जिनकी वजह से लोग अपने मानव समकक्षों की तुलना में बॉट साथियों को प्राथमिकता देते हैं। शायद एआई चौटबॉट विकसित करने में खर्च किए जा रहे अरबों का एक निश्चित प्रतिशत सामाजिककरण के सुलभ स्थल बनाने पर खर्च किया जा सकता है – पार्क, पुस्तकालय, मनोरंजन स्थल – जो सभी उम्र के लोगों को मानवीय संपर्क के जादू को फिर से खोजने में मदद कर सकते हैं। यह केवल एआई ही नहीं था जिसने सेवेल सेट्जर III को विफल किया यह समाज था।

खोखली बातों से नहीं बचेगी जैव विविधता

विनोद

अपने आसपास जो जैव विविधता हम देखते हैं उसे तैयार होने में दो से तीन अरब वर्ष लगे हैं। अत्यधिक उद्योगीकरण, उपभोक्तावाद, तीव्र अनियोजित कृषि एवं शहरीकरण से पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है। यह जलवायु में नकारात्मक परिवर्तन के रूप में हमारे सामने है। जैव विविधता का संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि समस्त जीव– जंतु, पादप, सरीसृप एक–दूसरे पर निर्भर हैं। विभिन्न प्रजातियों की आपसे सहजीविता प्रकृति के संतुलन के लिए जरूरी है। जैव विविधता की संपन्नता के लिए विख्यात कोलंबिया के कैली शहर में इन दिनों संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन चल रहा है। एक नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में 190 देशों के 12 हजार से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में 2022 में कनाडा के मांट्रियल में अपनाया गया कुनमिंग मांट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (जीबीएफ) एक बड़ी उपलब्धि है। कोलंबिया में इस संधि के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। कुनमिंग मांट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे में 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इनमें 30 प्रतिशत जमीन और समुद्री क्षेत्र की जैव विविधता की सुरक्षित करना तथा प्लास्टिक जनित प्रदूषण पर रोक सबसे प्रमुख हैं। जीबीएफ में ऐसे सब्सिडी पर रोक लगाने का भी उल्लेख है, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देती हो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह वैश्विक वार्ता इसलिए प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि यहां बनी सहमति का सीधा असर अजरबैजान में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कोप–29) में दिखेगा। प्रजातियों से बचेगी जैव विविधता जलवायु परिवर्तन भूमि और समुद्र में प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट पैदा करता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ने के साथ यह संकट और भी बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसर जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में प्रजातियों की संख्या में एक हजार गुना वृद्धि हो रही है यह मानव इतिहास में किसी भी अन्य समय की तुलना में कहीं अधिक है। वहीं दूसरी और अगले कुछ दशकों में दस लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा भी है। जंगल की आग, चरम मौसमी घटनाएं और आक्रामक कोट और बीमारियां जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य खतरे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ प्रजातियां स्थानांतरित होकर जीवित रह पाएंगे, पर अन्य नहीं जलवायु विविधता के नष्ट होने से मत्स्य पालन, फसलें और पशुधन के खत्म होने का खतरा रहता है। इससे उनकी उत्पादकता कम होती है। समुद्र के अधिक अम्लीय होने से अरबों लोगों को भोजन देने वाले समुद्री संसाधन सिकुड़ रहे हैं। कई आर्कटिक क्षेत्रों में बर्फ के आवरण में परिवर्तन ने पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने से खाद्य आपूर्ति को बाधित किया है। गर्मी से घस के मैदन और पानी कम हो सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और पशुधन प्रभावित हो सकता है। स्थानीय समुदाय को प्राथमिकता जैव विविधता के संरक्षण के लिए जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं, उनका क्रियान्वयन स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर निर्भर करता है। स्थानीय समुदाय उस क्षेत्र के पारिस्थितकी तंत्र एवं जलवायु से परिचित होते हैं। ऐसे में उनका पारंपरिक ज्ञान जैव विविधता के संरक्षण में उपयोगी साबित होता है। भारत आज पर्यावरण अनुकूल पहल के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है तो इसके पीछे समुदायों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता एवं प्राचीन परंपराएं हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार भारत में जंगली पौधें की 45,000 प्रजातियां हैं। इनमें से 7,500 प्रजातियां स्वदेशी स्वास्थ्य प्रथाओं के लिए औषधीय उपयोग में हैं। लगभग 3,900 पौधों की प्रजातियों का उपयोग आदिवासी भोजन के रूप में करते हैं। इनके अलावा कई पौधों का उपयोग लकड़ी, भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। 700 प्रजातियां नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सैंदर्य और सामाजिक दृष्टिकोण से सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। भारत ने दिखाई राह जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में भारत के पास साझा करने के लिए बहुत कुछ है। भारत ने नीतियों, नवाचार, सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग तंत्र विकसित करने की वकालत की है। हमारे पास विश्व के कुल भूमिक्षेत्र का 2.4 प्रतिशत है, लेकिन हमारी वैश्विक जातीय विविधता 8.1 प्रतिशत है। भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में 1972 में पारित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जहां मील का पत्थर साबित हुआ है, वहीं अन्य नीतिगत उपक्रमों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। इनमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट प्रोजेक्ट डाल्फिन प्रमुख नीतिगत पहल हैं। 20वीं सदी के मध्य तक देश में शिकार, मानवीय गतिविधियों एवं पर्यावास की कमी के कारण बाघों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही थी, लेकिन अब भारत विश्व के 70 प्रतिशत से अधिक बाघ का निवास है। भारत अपने संपूर्ण जीव–जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश है। इस सूची में कुल एक लाख चार हजार 561 प्रजातियां हैं। समुद्री जैव विविधता संरक्षण केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और निरंतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत ने सितंबर 2024 में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते (बीबीएनजे) पर हस्ताक्षर किया है। इसे हाईसीज संधि के नाम से भी जाना जाता है 100 से अधिक देश इस पर हस्तारक्ष कर चुके हैं। बीबीएनजे संधि समुद्री संसाधनों के दौहन में समावेशी पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है। इसपर हस्ताक्षर करने वाले देश को उच्च समुद्री क्षेत्र से हासिल किए गए संसाधनों का समुचित वितरण करना होगा। यह संधि समुद्री संरक्षित क्षेत्र, समुद्री प्रौद्योगिकी, दक्षता संवर्धन, पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन जैसे चार क्षेत्रों के लिए नियम बनाती है। बीबीएनजे समझौता संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत सदस्य देश पर अनिवार्य रूप से लागू होता है। समुद्री सीमा में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट पनडुब्बी संचलन और पाइपलाइन बिछाने आदि कार्य सभी के लिए खुले होते हैं। कुलमिलाकर जैव विविधता का संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन एक–दूसरे से संबंधित हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाकर ही जैव विविधता संरक्षण संभव है। जैव विविधता के समक्ष संकट की सबसे बड़ी वजह आक्रामक उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई एक पेड़ काटा जाता है तो न जाने कितने सूक्ष्म जीवों का पर्यावास नष्ट होता है। जैव विविधता नष्ट होने से आनुवंशिक विविधताएं खत्म होती हैं।

राज्य के विकास की नब्ज पर साय सरकार की मजबूत पकड़

पवन

संयुक्त संचालक जनसंपर्क छत्तीसगढ़ के नीति निर्धारकों को दो कारकों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है एक तो यहां की आदिवासी बहुल आबादी और दूसरी यहां की कृषि प्रधान अर्थव्यस्था। राज्य की नीतियां तय करते समय इन दोनों की अनदेखी नहीं की जा सकती, दोनों को ही बराबर महत्व देना पड़ता है। हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित देश में माओवादी आतंक के खात्मे के प्रति केन्द्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। केन्द्र के इस फैसले ने राज्य को समृद्धि के रास्ते में आगे जाने के संकल्प को और मजबूती दी है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। लगभग तीन करोड़ की आबादी वाला यह राज्य आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है। साय सरकार ने छत्तीसगढ़ की बागडोर संभालते ही राज्य के विकास की दिशा को तय करने वाले दो प्रमुख कारकों आदिवासी समुदाय और किसान दोनों पर शुरू से ही ध्यान दिया है। राज्य में लोगों को स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के वायदे को लेकर आयी साय सरकार आई.टी. और ए.आई आधारित प्रणाली को पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनाना शुरू कर दिया है। राज्य में कृषक उन्नति योजना खेती–किसानी के लिए एक नया संबल बनी है। इसके चलते कृषि समृद्ध और किसान खुशहाल हुए हैं। राज्य में खेती–किसानी को नई ऊर्जा मिली है। राज्य में उन्नत खेती को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार के किसान हितैषी फसलों का असर अब खेती–किसानी में साफ दिखाई देने लगा है। उन्नत कृषि यंत्रों का उपयोग खेती–किसानी में बढ़ा है। बीते खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, जिसके एवज में 32 हजार करोड़ रूपए भुगतान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प के अनुरूप राज्य के किसानों को दो साल के धान की बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान किया। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को धान की मूल्य की अंतर राशि के रूप में 13 हजार 320 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। इस तरह किसानों को कुल मिलाकर 49 हजार करोड़ रूपए सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किए गए। छत्तीसगढ़ में किसानों से धान खरीदी शुरू से ही चुनौतीपूर्ण रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने समर्थन मूल्य पर 14 नवम्बर से धान खरीदी करने जा रही है। धान उपार्जन केन्द्रों में छत्तीसगढ़ सरकार के दिशा–निर्देश के मुताबिक सभी तैयारियां की जा रही है। इस साल राज्य में बेहतर बारिश एवं अनुकूल मौसम के चलते धान के विपुल उत्पादन की उम्मीद है। इसको देखते हुए राज्य में समर्थन मूल्य पर 160 लाख मीटरिक टन धान उपार्जन अनुमानित है। राज्य में किसानों से 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी की जाएगी। राज्य के किसानों को खेती–किसानी के लिए वर्तमान खरीफ सीजन में 6500 करोड़ रूपए के अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के दिए जा चुके हैं। अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यहां के किसान अब ई–नाम पोर्टल (कृषि बाजार) के माध्यम से अपने उपज का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता, राज्य के किसानों से उनकी उपज खरीद सकेंगे, इससे उत्पादक किसानों को लाभ होगा। किसानों को उन्हें पंजीयन की जरूरत नहीं होगी।

आॅनलाइन खरीदारी के नुकसान जानना जरूरी

ललित

चाहे मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं कायर हूं। लेकिन फिर, बहुत सी चीजें जिनसे मुझे डर लगता है, आजकल हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही हैं, और मुझे उनसे निपटना मुश्किल लगता है। उदाहरण के लिए, तकनीक है। ऑनलाइन खरीदारी मुझे डराती है। कोविड आने तक मैंने कुछ हद तक इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी मैं सफल रहा। मैंने बहाने बनाए, जैसे, यह खरीदने से पहले कुछ देखने या महसूस करने जैसा नहीं है, और, आपको बाजार में मिलने वाले फल कभी भी उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, वगैरह। कोविड ने यह सब बदल दिया। बाजार जाकर भयानक बीमारी का जोखिम उठाना ऑनलाइन चीजें खरीदने से कहीं ज्यादा डरावना था। इसके अलावा, मेरी पत्नी प्रीता ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं डरती थी। उसने इसे पानी में बत्तख की तरह अपनाया, और जल्द ही हम आराम से साथ रहने लगे। हमें सामान डिलीवर करने वाले युवकों को देखने की भी जरूरत नहीं थीरू उन्होंने बस घंटी बजाई और सामान हमारे लिए पोर्च में टेबल पर छोड़ दिया। व्यावहारिक रूप से हमें जो कुछ भी चाहिए था वह हमारे दरवाजे पर उपलब्ध था, और, जबकि बाहर खाना असंभव था, हमारे पसंदीदा रेस्तरां ने डिलीवरी की, इसलिए हमें शायद ही कभी कमी महसूस हुई। कोविड कम हो गया, लेकिन प्रीता को अपने सोफे पर आराम से चीजें खरीदना पसंद था, अपनी सारी खरीदारी के लिए अपने सेलफोन का इस्तेमाल करना। मेरे आग्रह के बावजूद, उसने यह अभ्यास जारी रखा क्योंकि यह बहुत सुविधाजनक था। और फिर वह समय आया जब उसका फोन खराब व्यवहार करने लगा। यह समय–समय पर बंद हो जाता था, और बहुत धीरे–धीरे काम करता था। "यह तीन साल पुराना है," उसने मुझे एक शाम बताया। "दिन–ब–दिन धीमा होता जा रहा है। नया लेने का समय आ गया है।" "चलो चलते हैं," मैंने कहा। "कहाँ?" उसने पूछा। "दुकानों पर," मैंने कहा। "क्या आपको नया सेलफोन नहीं चाहिए?" "बिल्कुल नहीं," उसने कहा, अपने पसंदीदा आरामकुर्सी पर फोन को हाथों में लेकर और अपने अंगूठे दौड़ाते हुए। "जब तक यह अभी भी चल रहा है, तब तक नहीं। आधे घंटे बाद, उसने घोषणा की। "देखो मैंने क्या खरीदा?" "क्या?" मैंने पूछा। उसने मुझे एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर डील दिखाई, जो ए से जेड तक कुछ भी डिलीवर करने का वादा करती है। एक नया फोन, उसके मौजूदा फोन से ज्यादा तेज और चमकदार, उचित कीमत पर, और इसके अलावा, पुराने फोन के बदले में एक अच्छी ट्रेड–इन वैल्यू। बहुत बढ़िया, मैंने कहा। देखा? उसने कहा। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि यह अब से तीन दिन बाद आ जाएगा। बहुत बढ़िया! मैंने कहा, उस भविष्य से बचते हुए जिसमें मैं अपनी सभी खरीदारी के लिए उस पर निर्भर था। हालांकि, अगले दिन हमें कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था। तुम्हारे फोन का क्या? मैंने पूछा। कोई चिंता नहीं, उसने जवाब दिया। डिलीवरी बॉय यह पुष्टि करने के लिए कॉल करेगा कि हम घर पर हैं या नहीं, और हम उसे अगले दिन लाने के लिए कहेंगे। लेकिन डिलीवरी बॉय ने कभी कॉल नहीं किया। इसके बजाय, जब उसने फॉलो–अप किया, तो उसे ऑनलाइन साइट के ऐप पर एक संदेश मिला कि डिलीवरी बॉय ने कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं हो पाई। बकवास! वह गुस्से में बोली। उसने कभी कॉल नहीं किया! कितनी भयानक सेवा! ठीक है, मैंने कहा। तो अब हम क्या करें? बेशक, शिकायत करें! उसने कहा। अभी! हम उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकते! वह सोफे पर बैठ गई और इंटरनेट मार्केटिंग साइट का ग्राहक संबंध पृष्ठ ढूँढ़ लिया, जहाँ, कई विकल्पों को देखने के बाद, वह एक विकल्प पर क्लिक

करने में सफल रही जिसने कॉलबैक का अनुरोध किया। उन्होंने जल्द ही कॉल किया। उसने बताया कि क्या हुआ, और, थोड़ी देर की खामोशी के बाद, उसकी आवाज ऊँची हो गई। एक या दो मिनट चिल्लाने से उसे बेहतर प्रतिक्रिया मिली, और बहुत जल्द यह स्पष्ट हो गया कि ऑर्डर रद्द करने के अलावा कुछ नहीं बचा था, जो उसने किया। जब उसने फिर से वही ऑर्डर देने की कोशिश की – आखिरकार यह एक अच्छा सौदा था – तो उसने पाया कि वह फोन एक्सचेंज नहीं कर सकती। ग्राहक सेवा के साथ एक और चौट के बाद उसने पाया कि साइट ने उसके फोन के प्डम्प् नंबर को वर्जित सूची में दर्ज कर दिया था, इसलिए वह इसे अगले दस दिनों तक एक्सचेंज के लिए नहीं रख सकती थी। फिर से चिल्लाने की होड़ लगी, जिसके बाद इसे सूची से हटा दिया गया। यह कब आएगा? मैंने पूछा। चार दिन, उसने तारीख बताते हुए कहा। चार दिन बीत गए, लेकिन फोन नहीं आया। उसने फिर से ग्राहक सेवा से कॉलबैक के लिए कहा, और एक बार फिर डील रद्द कर दी। मैं हार मानती हूँ, उसने कहा। मुझे लगता है कि मैं कुछ और समय के लिए इस फोन के साथ रहूँगी। उसने अपना बहुत सारा डेटा डिलीट कर दिया और कई ऐसे ऐप हटा दिए जिनका वह नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करती थी।

नाट्य कलाओं से हमे जीवन जीने की कला मिलती है - वंदना पटेल

सुजानगंज। क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहरियाँव मे चल रहे नव युवक मंगल दल नाट्य समिति द्वारा नाटक

के दूसरे दिन चंडालीन सास और अय्याश पति नामक का नाटक खेला गया जहां पर इस नाटक को देख क्षेत्रीय लोगों ने खूब सराहा. वहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वंदना पटेल जिला मंत्री भाजपा ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि नाटक खेलना आज के समय में बहुत ही कठिन हो गया है क्युकी ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप कोई भी सामाजिक कार्य करना चाहेंगे तो तमाम लोग रोकने वाले मिल जाते हैं तो यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और इससे हमे अपने जीवन जीने की कला सीखने को मिलती है. वहीं पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल समाजसेवी मणि शंकर यादव ने कहा कि आज के युग में यदि युवा पीढ़ी कुछ भी ठान लें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है क्युकी भारत के युवाओं ही इतिहास रचा है तो आज की युवा पीढ़ी के अंदर वह जज्बा है जो चाहें वह कर सकता है. इस अवसर पर राय साहब पटेल, रजनीकांत पटेल, शिव सागर पाल, महेंद्र पटेल, राजेश पटेल आदि लोग उपस्थित रहे।

'पीड़ित को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता – सुनील कुमार दुबे'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने व अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एसपी नीरज जादौन ने 03 नवंबर को कई थाना प्रभारी के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया था। इसी क्रम में पिहानी कोतवाली से स्थानांतरित होकर आये थाना पाली के नवागत प्रभारी निरीक्षक चार्ज संभालने के बाद एक्शन में दिखे दुबे जी ने क्षेत्र की जनता और पुलिस के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की बात कहते हुए जनता की रक्षा एवं उन्हें न्याय दिलाना अपना परम कर्तव्य एवं पहली प्राथमिकता बताया।आपको बता दें कि जनपद वाराणसी के मूल निवासी 2001 बेच के तेज तर्रार नवागत प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार दुबे ने अपनी प्राथमिकताओं से अवगत कराते हुए कहा कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। अपराधियों को किसी हाल में नहीं बख्शा जायेगा लिहाजा वह शराफत की जिंदगी जियें या फिर जेल जाने को तैयार रहें। प्रभारी निरीक्षक दुबे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वह पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में कोई निर्दोष जेल नहीं जायेगा जबकि दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जायेगा। यदि किसी को कोई समस्या है तो वह निःसंकोच थाने में आकर पुलिस की मदद ले।उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में कुछ भी गलत दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते किसी भी छोटी बड़ी वारदात को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि पत्रकार और पुलिस के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण से अपराध पर अंकुश लगेगा। पत्रकार और पुलिस के मध्य सूचनाओं का नियमित आदान प्रदान होता रहेगा। सूचनाओं की पुष्टि के लिए दूरभाष पर सम्पर्क अवश्य करें।

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने लोनी रामलीला मेला का किया उद्घाटन

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने 12 दिवसीय लोनी रामलीला मेला का फीता काटकर एवं दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि भगवान राम के आदर्श को जनता तक पंहुचाने का सबसे उचित माध्यम रामलीला का मंचन होता है। इसलिए लोगों को ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। उन्होने कहा कि मनुष्य को भी अपने अंदर अंहकार नहीं पालना चाहिए। अंहकांर ही मनुष्य को एक दिन खत्म कर देता है। लंकापति रावण अंहकार के कारण ही भगवान राम के हाथों मारा गया। इसलिए समाज में लोगों को अंहकार से दूर रहना चाहिए। हमेशा भगवान राम के सिंद्धातों को अपनाना चाहिए, कहा कि मेला में पुराने सभी लोग मिल जाते हैं मेला आपकी सौहार्द एवं मिलन को बढ़ावा देता है। रामलीला के आयोजन से हमें सीख लेने चाहिए, क्योंकि श्रीराम के आदर्श से लोगों को प्रेरणा मिलती है।राज्य मंत्री ने कहा कि भगवान राम के आदर्श पूरे संसार के लिए अनुकरणीय हैं। इन आदर्शों पर चलकर विश्व बंधुत्व की भावनाओं को मजबूत किया जा सकता है। बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे मिल सकती है। इसका महत्व रामलीला के माध्यम से ही पता चलता है। इस पर अवसर पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक नवनीत गुप्ता,ब्लॉक प्रमुख टोडरपुर प्रतिनिधि श्यामू त्रिवेदी, पवन रस्तोगी, समाजसेवी सरोज मिश्र, आजाद सिंह,अनुराग श्रीवास्तव, सभासद प्रतिनिधि रामकांत मौर्य, रचित गुप्ता, योगेंद्र यादव,सोनू, लोनी रामलीला कमेटी प्रबंधक रजनीश बाजपेई, उपाध्यक्ष श्याम किशोर पांडेय , महामंत्री विमल कुमार पांडेय, कोषाध्यक्ष सर्वेश कुमार पांडेय, ब्रजभान कश्यप, संचालक राजेश पाण्डेय, वीरेन्द्र द्विवेदी, अंकित त्रिवेदी, जितेंद्र द्विवेदी ,मनोज त्रिवेदी ,अंशुल श्रीवास्तव, सौरव पांडेय, देवेश पांडेय, अमन पांडेय, गंगाराम पाल, विकाश पांडेय, विजय मिश्रा, विपिन राठौर, मदन, गंगाराम , राजेश राठौर, ग्राम प्रधान लोनी राम प्रताप पाल तथा समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे।

मारिफ अली खान (अध्यक्ष) चुने गए

ई–रिक्शा एण्ड ई–ऑटो चालक/मालिक संयुक्त मोर्चा

मृत्युंजय प्रताप सिंह पत्रकार

लखनऊ। श्रीमती ममता तिवारी, अध्यक्ष व मारिफ अली खान ने संयुक्त प्रेसवार्ता करके ई–रिक्शा एण्ड ई–ऑटों चालक/मालिक संयुक्त मोर्चा, लखनऊ जिसकी अध्यक्षता श्रीमती ममता तिवारी स्वयं होगीं व ई–रिक्शा व ई–ऑटों महासंघ, लखनऊ के गठन का ऐलान किया। इस संगठन के अध्यक्ष मारिफ अली खान होगें, जिन्हें शहर के 12 से अधिक संगठनों ने उनको अपना नेता (अध्यक्ष) चुना। श्रीमती ममता तिवारी ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए बताया कि दोनों संगठन मिल–जुलकर कार्य करेंगे और ई–रिक्शा चालक के व्यवसाय प्रबन्ध व समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेंगे।

उन्होने बताया कि ई–रिक्शा चालकों के साथ हो रहे दुर्व्यहार और रोड पर कई समस्याओं को लेकर जैसे पानी, शौचालय, पिकप स्टैण्ड व चार्जिग जैसी समस्याओं को लेकर व परेशान व प्रताड़ित रहते हैं। पहले 2014 में ई–रिक्शा का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था। बिना रजिस्ट्रेशन के ही ई–रिक्शा चलाये जाते थे। यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ जगहों पर ई–रिक्शा का नगर निगम से रजिस्ट्रेशन हुए, परन्तु कुछ समय बाद वह भी बन्द हो गये। इन सबको ध्यान में रखकर समस्त एसोशियन की मौजूदगी में मोहम्मद वासिफ की अध्यक्षता में एक संयुक्त मोर्चा का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें सर्व सम्मति से श्रीमती ममता तिवारी को अध्यक्ष चुना गया। पूर्व में जो फर्जी ई–रिक्शा संयुक्त मोर्चा बनाया गया था। समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि तत्कालीन अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव व अन्य पदाधिकारियों के नाम ज्ञात हुए है कि जिसकों अधिकारियों ने स्वीकार करते हुए उनके साथ बैठके करने लगे, जबकि शहर में लगभग 15 से अधिक एसोशियन ६ यूनियन है। फर्जी संयुक्त मोर्चा अधिकारियों के साथ बैठक कर उनकों गुमराह करता रहा और फोटो खिचवाकर अपना प्रचार करता रहा। उन्हीं फोटो को दिखाकर लोगों को स्टैण्ड के नाम से वसूली शुरू कर दी, जिससे आहत होकर संयुक्त मोर्चा में शामिल आसिफ शेख, प्रचार मंत्री व सदस्य मोहम्मद वासिफ ने संयुक्त मोर्चा से त्याग पत्र दे दिया।

शहर में लगभग 53 हजार ई–रिक्शा, लगभग 10 हजार ई–ऑटों, लगभग 05 हजार सी०एनजी० ऑटों लगभग 02 हजार सी०एन०जी० टैम्पों टैक्सी कुल 70 हजार तिपहिया वाहन है जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए हर तरह की समस्याओं से जूझ रहे है। फर्जी संयुक्त मोर्चा के विरूद्ध जॉच कराकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए इनका पंजीयन निरस्त करने की मांग करते है। ई–रिक्शा चालक की इन्हीं समस्याओं के लिए संगठन का गठन किया गया है।

दो दिवसीय गोमती महोत्सव का आयोजन किया गया

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था मां फाउंडेशन व फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन द्वारा गोमती नदी के तट पर दो दिवसीय गोमती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सम्मिलित हुए जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा व विशिष्ट अतिथि जिला सहकारी बैंक चेयरमैन कुँवर वीरेंद्र सिंह संस्था संरक्षक व्यापारी नेता इन्द्रभान सिंह श्इंदुश ने सामुहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तत्पश्चात स्वच्छ गोमती अभियान द्वारा गोमती आरती कर आदि गंगा माँ गोमती को प्रदुषित न करने के संकल्प के साथ 1111 आटे से निर्मित दीप दान किया गया। संस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति विभिन्न राज्यों से आए तमाम कलाकारों द्वारा प्रचलित लोक कला लोक विधाओं का प्रदर्शन किया गया इसको देखकर श्रोता मंत्रमुग्ध होते रहे जिसमें प्रमुख रूप से शैलेश दुबे बिहार, हरिओम तिवारी सुर संग्राम, राजकुमार यादव सुर संग्राम, हास्य एवं व्यंग्य के कवि राधेश्याम भारती, श्वेता प्रियंशि, बिट्टू किन्नर, कठघोड़वा नृत्य, विकास रागी, अभिषेक मयंक, कृष्णा मौर्य नीतेश सिंह, सविता मौर्य शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विमल सिंह महादेव सेना, शिराज अहमद आसरा द होप ट्रस्ट, उर्वशी सिंह अतुल्य वेल्फेयर ट्रस्ट, अंजना सिंह राष्ट्रीय हिन्दू भगवा वाहिनी, लेखक एवं कवि जयंती प्रसाद जगमग, लेखिकाध्समाजसेविका डॉ. ज्योति दास, संगीत घराने से पंडित सूर्य प्रकाश मिश्र ष्बल्ला गुरुष् अभिनेता आशीष माली, लोकगायक गुलाब राही आदि को सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में बतौर अतिथि पूर्व विधायक डॉ हरेंद्र प्रसाद सिंह, नगर पालिका परिषद जौनपुर के पूर्व अध्यक्ष दिनेश टण्डन, अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉ. राम सूरत मौर्य, ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि मम्मन यादव, डॉ. मनोज वत्स,निखिलेश सिंह सम्मिलित हुए। आयोजक संस्था उपाध्यक्ष सुधांशु सिंह, प्रणविजय सिंह, अजय यादव व नित्यानंद पांडेय ने समस्त आगंतुकों का स्वागत किया संस्थाध्यक्ष दीपक सिंह पत्रकार, अवधेश श्रीवास्तव, अगम यादव ने आभार व्यक्त किया व संचालन सलमान सेख ने किया।

पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या पर न्याय की मांग को लेकर इंडियन कौंसिल ऑफ प्रेस ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। फतेहपुर के पत्रकार दिलीप सैनी की निर्मम हत्या के विरोध में मंगलवार को अयोध्या जिले के पत्रकार सड़को पर उतर आए।इंडियन कौंसिल आफ प्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन की ओर से दोषियों को फांसी देने की मांग की गई है।उन्होंने एक स्वर में दिलीप सैनी की हत्या के पीछे जिम्मेदार अपराधियों को फांसी देने की मांग करते हुए पत्रकारों ने न्यायपालिका और प्रशासन से पीडित परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इंडियन कौंसिल आफ प्रेस के प्रदेश सचिव सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। यदि पुलिस सतर्क होती तो इतनी बड़ी घटना न होती। जिलाध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुऐ प्रशासन पत्रकारों को सुरक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराये जिससे पत्रकार बिना भय के निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। ज्ञापन देने

वाले पत्रकारों में जिसमें संगठन के जिलाध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव, संगठन मंत्री राजेन्द्र दूबे, जिला उपाध्यक्ष रविकान्त आर्य, जिला महासचिव खालिद रशीद, संरक्षक कुशल मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष बिस्मिल्ला खान सहित इंडियन कौंसिल ऑफ प्रेस के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे।

हवलदार इंदल सिंह, सेना मेडल, (सेवानिवृत्त) पूर्व सैनिक के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कारित अत्याचार करने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, भारत के सभी जनपदों एवं प्रांतों में राष्ट्र प्रथम के सेवा भाव से समर्पित एक विशाल राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संगठन है। जो कि वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की देखभाल एवं सरकार, शाशन व प्रशासन की धर्मनिरपेक्षता से सहायता करता है। यह घटना पूर्व सैनिक हवलदार इंदल सिंह, सेना मेडल, (सेवानिवृत्त), 19 राजपूत रेजीमेंट, ग्राम सेंदुरा मऊ, पोस्ट राधा बालमपुर थाना डलमऊ जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश की है। दीवाली के पावन पर्व पर पूर्व सैनिक इंदल सिंह के पुत्र का पटाखे को लेकर किसी अन्य बच्चे से झगड़ा हो गया था। तभी दूसरे बच्चे ने पूर्व सैनिक इंदल सिंह के बच्चे के सर पर डंडे से भीषण प्रहार किया। इंदल सिंह को पता लगते ही विवाद को सुलझाने का प्रयास करने लगे तभी संबंधित थाने की पुलिस ने पूर्व सैनिक इंदल सिंह को कोठरी में बंद कर गंभीर शारीरिक प्रताड़नायें दी। डलमऊ थाने का पूर्व सैनिक के प्रति ऐसा रवैया देख उत्तर प्रदेश अपितु संपूर्ण भारत के सभी पूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश पुलिस के बर्बरता पूर्ण व्यवहार से स्तब्ध एवं क्षुब्ध है। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय कमेटी से जाँच करवाकर हवलदार इंदल सिंह सेना मैडल (सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार को न्याय दिलाने एवं दोषियों के विरूद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिक व उनके परिवार आजीवन आपके आभारी रहेंगे।

डाला छठ पूजा भारतीय पर्व त्यौहार – वैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक आधार – अखिलेश्वर शुक्ला

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। बिहार के प्रमुख पर्व में शुमार डाला छठ का पर्व अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाने लगा है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो बीते कई वर्षों से डाल अच्छा की धूम मची हुई है जनपद जौनपुर के गोमती नदी सही नदी यो आदि पर भारी संख्या में महिलाएं

व्रत करती हैं और छठ माता की पूजा करती है। भारतीय ब्रत–पर्व–त्योहार पर जब हम सभी गम्भीरता पूर्वक चिंतन मनन अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि मौसम (जाड़ा– गर्मी–बर्षा) एवं प्रकृति में ऋतुओं के साथ साथ खेत –खलीहान के अनाज – पैदावार से भारतीय पर्व–त्योहारों का बदलते मौसम के साथ गहरा रिश्ता है। इस तरह की बातों को हम भले हीं गम्भीरता से न लें , न समझें –लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है।

जहां तक दार्शनिक सामाजिक आर्थिक आधार की बात की जाय तो प्रकृति प्रेम, स्वास्थ जीवन, सामाजिक सौहार्द, आर्थिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने में इन पर्व त्यौहारों की अहम भूमिका होती है। जिसे हम बहुत आसानी से, सतही तौर पे नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें शोध परक दृष्टि का अवलंबन लेना होगा।

जहां तक छठी माता के ब्रत का विधान है,जो तीन दिन पूर्व से कुल चार दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। पहले ऐसा कहा जाता था कि यह बिहार प्रांत में मनाया जाता है। लेकिन इसके व्यापकता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि दिल्ली सहित कुछ प्रदेशों की सरकारें अवकाश घोषित करने से लेकर घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा एवं प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने को मजबुर है। यहां तक कि पश्चिमी देशों में रह रहे भारतीय भी यथा संभव जलाशय की ब्यवस्था करके विदेशी धरती पर भी धूमधाम से डाला छठ पूजा करते देखे जा सकते हैं। इस संबंध में बुधवार को बात करते हुए मूल रूप से बिहार निवासी पूर्व प्राचार्य प्रो अखिलेश्वर शुक्ला ने इसके महत्वके बारे में बताते हुए बताया कि चार दिवसीय यह ब्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाय अर्थात परिवार सहित स्वयं ब्रति के स्वच्छता , खान–पान में संयम एवं जलाशय में घाट की सफाई एवं पूजा का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है।

दुसरे दिन पंचमी तिथि को ष्खरनाष् अर्थात पुरे दिन ब्रत रहकर सायं में मीठा भात (खीर/जाऊर)खाकर अखण्ड छठी माता का व्रत उपवास प्रारम्भ हो जाता है। तीसरे दिन षष्ठी तिथि को व्रती महिलाएं/पुरुष जलाशय में खड़े होकर अस्ताचलगामी (डुबते हुए) सूर्य को अर्घ्य देकर संतान , समृद्धि, सुख, शांति की का यहमना करते हैं। चौथे दिन सप्तमी तिथि को उदीयमान (प्रातः उगते सूर्य) को अर्घ्य देकर देकर घाट पर उपस्थित जनों को प्रसाद वितरित करके स्वयं पारन (अन्न ग्रहण) करते हैं।

वास्तव में चार दिवसीय इस व्रत की तैयारी हफ्ते भर पहले से शुरू हो जाती है।

जहां तक इस व्रत में जिस छठी माता की पूजा की जाती है वह सूर्य देव की बहन और बाबा भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय जी की पत्नी हैं। जिन्हें सृष्टि एवं प्रकृति की देवी के रूप में जाना जाता है। प्रो अखिलेश्वर शुक्ला ने कहा कि –छठ पूजा में डुबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करने की परम्परा से हमें सबक लेना चाहिए। साथ ही उगते सूर्य देव को दूध से जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है।

जेसीपी ने हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली का किया शुभारम्भ

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। Jt.CP L-O ने यातायात माह नवम्बर 2024 के अवसर पर पुलिस लाईन की परेड ग्राउंड में स्कूल के छात्र–छात्राओं व आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया एवं हरी झंडी दिखाकर यातायात जागरूकता रैली का शुभारम्भ किया।

सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय योगी सरकार को वापस लेना होगा – वंशराज दुबे (मुख्य प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश)

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को लेकर हाल ही में मीडिया में आई खबरों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना बनाई गई है। यह योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा 2020 तक बंद किए गए 26,000 स्कूलों के बाद अब एक नया कदम है। यह फरमान, जो 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का है, न केवल सरकार की नीतियों को संदिग्ध बनाता है बल्कि यह सीधे तौर पर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जानकारी अखबारों के माध्यम से दी कि इन स्कूलों को षनिकटवर्ती स्कूलों में विलयष कर दिया जाएगा, जिसे योगी सरकार ने भ्रामक और निराधार करार दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कदम सरकारी स्कूलों को समाप्त करने की एक सोची–समझी साजिश है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में इसका उदाहरण साफ देखा जा सकता है, जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 6 स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह केवल एक कागजी दलील नहीं, बल्कि एक ठोस कार्य योजना है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। हम जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 21। के तहत हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन कानून कहता है कि हर बच्चे को शिक्षा की सुविधा 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के भीतर अपर प्राइमरी स्कूल के रूप में मिलनी चाहिए। लेकिन इस निर्णय से यही स्पष्ट होता है कि योगी सरकार न

केवल इस कानून का उल्लंघन कर रही है, बल्कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 52,000 स्कूलों को बंद करने का निर्णय क्यों लिया? इसका सीधा सा उत्तर है कि यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने, गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने और शिक्षा के अधिकार को समाप्त करने की एक साजिश है। हम यह भी देख रहे हैं कि न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड और अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 23,000, असम में 8,000 और उत्तराखंड में 1,100 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। यह न केवल राज्य सरकारों की विफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भाजपा द्वारा शासित राज्य शिक्षा के नाम पर एक बड़ा हमला कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस कदम का पुरजोर विरोध करती है। हम यह मानते हैं कि सरकार का कर्तव्य है कि वह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे, न कि उन्हें इस अधिकार से वंचित करे। आने वाली 9 तारीख को आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेगी और योगी सरकार के इस दमनकारी निर्णय के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगी। आम आदमी पार्टी की यह लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि यह गरीब, दलित और पिछड़े बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले, और हम इस तरह के भ्रामक फैसलों को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे।

अब डीजीपी की सीधे नियुक्ति कर सकेगी राज्य सरकार

लखनऊ, संवाददाता। प्रदेश में अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में

सोमवार को कैबिनेट ने इस बाबत पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश के पुलिस बल प्रमुख) चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में मनोनयन समिति गठित करने का प्राविधान किया गया है। वहीं डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है। मनोनयन समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित अधिकारी, उप्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित अधिकारी, अपर मुख्य सचिव गृह, बतौर डीजीपी कार्य कर चुके एक सेवानिवृत्त डीजीपी सदस्य होंगे। इस नियमावली का उद्देश्य डीजीपी के पद पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के चयन के लिए स्वतंत्र एवं पारदर्शी तंत्र स्थापित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका चयन राजनीतिक या कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त है। साथ ही प्रदेश की विशिष्ट दशाओं तथा पुलिसिंग आवश्कताओं के अनुरूप भी है। डीजीपी का चयन राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए उनकी सेवा अवधि, सामान्यतरू बहुत अच्छे सेवा रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर किया जाना प्राविधानित किया गया है। मनोनयन समिति उन अधिकारियों के नाम पर विचार करेगी, जिनकी सेवानिवृत्ति में छह माह से अधिक शेष है। केवल उन नामों पर ही विचार किया जाएगा, जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 में डीजीपी के पद पर कार्यरत हैं।

हटाने का भी अधिकार

डीजीपी को पद से हटाने से संबंधित प्राविधानों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिशा–निर्देशों का पालन किया गया है। किसी आपराधिक मामले में या भ्रष्टाचार के मामले में, या यदि वह अन्यथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने में विफल है, तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों को लेकर दायर याचिका पर पारित निर्णय एवं आदेश के मुताबिक राज्य सरकारों से एक नवीन पुलिस अधिनियम बनाने की आशा की गई थी, ताकि पुलिस व्यवस्था को किसी भी दबाव से मुक्त रखा जा सके।

साथ ही नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के साथ विधि का शासन स्थापित किया जा सके। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों डीजीपी की नियुक्ति करने पर 8 राज्यों का अवमानना का नोटिस जारी किया था। इसमें यूपी भी शामिल था।

बसपा को खोखला कर रहा है दलित वोटों का बिखराव

लखनऊ, संवाददाता। उप चुनाव में अकेले दम पर उतरी बहुजन समाज पार्टी के लिए दलित वोट बैंक के बिखराव को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। पार्टी के तमाम प्रयासों के बावजूद दलितों का रुझान अन्य दलों की तरफ दिखाई पड़ रहा है। भाजपा, कांग्रेस और सपा के बाद अब आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) भी बसपा को उपचुनाव में नुकसान पहुंचाने की जुगत में है। बता दें कि बसपा का वोट बैंक बीते एक दशक के दौरान आधा हो चुका है। इसकी मुख्य वजह भाजपा रही, जिसने 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा के वोट बैंक में गहरी सेंध लगाई थी। हालांकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से बसपा को फायदा हुआ था और उसके 10 प्रत्याशी जीतकर सांसद बने थे। इसके बाद बसपा ने दोबारा अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका यह फैसला गलत साबित हुआ और वोटरों ने दोबारा अन्य दलों में विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बसपा से नगीना सीट छीन ली। वहीं पार्टी को वर्ष 2014 के चुनाव की तरह किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। इसकी मुख्य वजह दलित वोटरों का बसपा से मोहभंग होना माना जा रहा है। अब देखना यह है कि लगातार एससी–एसटी आरक्षण के उपवर्गीकरण का विरोध कर रही बसपा का साथ दलित वोटर देंगे कि नहीं।

लखनऊ के अवध बस डिपो सहित प्रदेश के 15 बस डिपो अब निजी हाथों में गए

लखनऊ, संवाददाता। अवध डिपो सहित रोडवेज ने पंद्रह डिपो निजी हाथों में सौंप दिए हैं। इन डिपो में बसों की मेंटीनेंस का काम अब निजी कंपनियां देखेंगी। अवध डिपो के अतिरिक्त नजीबाबाद, हरदोई, जीरो रोड, ताज डिपो, देवरिया, साहिबाबाद, वाराणसी कैंट, सुल्तानपुर, झांसी, बलिया, बांदा, बदायूं, हटावा और बलरामपुर डिपो शामिल हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि रोडवेज कार्यशालाओं की दक्षता बढ़ाने के मंतव्य से 19 डिपो के वर्कशॉप को आउटसोर्सिंग के जरिए टेंडर किया गया था।

इसमें 15 डिपो की निविदा को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 15 डिपो में कुल 1,255 बसों के लिए दरें 3:57 रुपये प्रति किमी से लेकर 5:48 रुपये तक प्राप्त हुए हैं। इस निविदा के जरिये से इन डिपो की वर्कशॉप में बसों की मरम्मत का काम निजी कंपनियों को दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से श्याम इंटरप्राइजेज, एसडीएल एंटर प्राइजेज, आरके ऑटो मोबाइल शामिल हैं। इनकी कार्यप्रणाली को देखने के बाद शेष सौ डिपो में बसों की मेंटीनेंस का काम भी निजी कंपनियों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यशालाओं में तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी के कारण परिवहन निगम की बसों में मेंटीनेंस की समस्या देखने को मिल रही है। प्राइवेट कंपिनयां अच्छी गुणवत्ता के साथ बसों की मेंटीनेंस करेंगी।

69000 शिक्षक भर्ती मामला- अभ्यर्थियों ने सीएम की पीएम से मुलाकात को बताया चुनावी

लखनऊ, संवाददाता। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को अभ्यर्थियों ने चुनावी मुलाकात बताया है, क्योंकि यह मामला प्रदेश सरकार का है इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका ही नहीं हैं। प्रदेश सरकार चाहे तो इस मामले का तत्काल समाधान हो सकता है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बयान जारी कर कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू कराने में हुई विसंगति को दूर करने का मामला विधानसभा उपचुनाव से पहले निकालने की बात बेमानी है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी ओबीसी समाज के कई नेता प्रधानमंत्री से मिले थे और हल निकाले जाने का आश्वासन दिया था। किंतु आज तक हल नहीं निकल पाया। यही कारण है कि हमें इस बार भी यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्याय देना ही चाहते थे तो हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आने पर क्यों नहीं दिए। उस समय प्रदेश सरकार और विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे रहे, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यूपी में उपचुनाव आया तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी याद आने लगे।

राहुल से मिलेंगे अभ्यर्थी

69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को रायबरेली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी से मिलेगा। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता ने बताया कि चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी राहुल से मिलकर न्याय दिलाने की मांग करेंगे। वहीं सोमवार को अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले में देवरिया में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से भी मिला है।

बच्चों के परख सर्वेक्षण के साथ गुरुजी की भी परीक्षा

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी में माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई और सीआईसीएसई बोर्ड से संचालित स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा छह से नौ तक के बच्चों का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण होना है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चार दिसंबर को परीक्षा का आयोजन होगा। बच्चों की परख परीक्षा के साथ ही गुरुजी की भी परीक्षा होगी। इससे पता चल सकेगा कि आखिर शिक्षकों ने बच्चों को कैसी शिक्षा दी है। कक्षा 6 और 9 के छात्र–छात्राओं की भाषा, गणित, परिवेश ज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय की परख एप से दक्षता परखी जाएगी।

इस परीक्षा में राजधानी के माध्यमिक शिक्षा परिषद के 850 स्कूल कॉलेजों के साथ सीबीएसई व सीआईएससीई के 301 विद्यालयों के बच्चे शामिल होंगे। परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता को मापना है, ताकि उनकी पढ़ाई बेहतर करने के लिए आगे उस पर ध्यान दिया जा सके।

राजकीय और एडेड के सामने चुनौती

शहर में संचालित 55 से अधिक राजकीय व 100 एडेड कॉलेजों में परीक्षा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती होगी। कुछ संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो दो दर्जन राजकीय कॉलेजों में बच्चों का कोर्स ही नहीं पूरा हो सका है। वहीं एडेड 80 एडेड कॉलेज तो ऐसे हैं जहां पर बच्चों की पढ़ाई अक्सर प्रभावित रहती है। इन कॉलेजों में शिक्षकों की समय से रेग्युलर उपस्थिति भी मुश्किल होती है।

निजी स्कूलों की तर्ज पर करानी होगी तैयारी

सरकारी कॉलेजों की अपेक्षा निजी कॉलेजों के बच्चे आगे निकल सकते हैं। ऐसे में सरकारी कॉलेजों में बच्चों की तैयारी भी निजी स्कूलों की तर्ज पर करनी होगी।

इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक ने एडेड व राजकीय कॉलेजों को प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर बेहतर तैयारी कराने के लिए कहा है।

गड़बड़ मिली सड़क तो जेई से लेकर कांट्रेक्टर तक पर होगी कार्रवाई, धार्मिक जगहों पर हों अच्छी रोड

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर अवर अभियंता (जेई) से लेकर मुख्य अभियंता तक सभी की जवाबदेही तय होगी। अनुबंध के नियमों का उल्लंघन होगा तो कांट्रेक्टर या फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। ठेका लेकर दूसरे को ठेका देने की व्यवस्था स्वीकार न करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण की परियोजना तैयार करते समय स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखें। प्रत्येक परियोजना के लिए समयबद्धता और गुणवत्ता अनिवार्य शर्त है, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। सीएम ने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के साथ ही काम शुरू करने और खत्म होने की तिथि सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए। फिर इसका कड़ाई से पालन किया जाए। बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पूरे हो चुके कामों का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उसकी उपयोगिता का आकलन जरूर किया जाए। प्राथमिकता तय करें, फिर मेरिट के आधार पर किसी सड़क या सेतु निर्माण की स्वीकृति दें। विकास कार्यों का लाभ सभी 75 जिलों को मिले।

ब्लॉक तक दो लेन मार्ग अनिवार्य

सीएम ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय तहसील व ब्लॉक मुख्यालय योजना के अंतर्गत सभी तहसील व ब्लॉक मुख्यालय को जिला मुख्यालय से न्यूनतम दो लेन मार्गों से जोड़े जाने का काम तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भव्य मैत्री द्वार बनाने का कार्य तेजी के साथ पूरा कराएं। जहां भूमि उपलब्ध न हो, वहां तत्काल स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। अब तक 96 मार्गों पर प्रवेश द्वार पूरे हो चुके हैं या निर्माणाधीन हैं।

एफडीआर तकनीक से बनाएं 6 हजार किमी सड़कें

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की सड़कों का निर्माण अब लोक निर्माण विभाग करवा रहा है। सीएम ने कहा कि इन कामों को प्राथमिकता दें। यहां गड्ढे नहीं होने चाहिए। अभी लगभग 6000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इन्हें एफडीआर तकनीक से बनाया जाना चाहिए।

सीएम ने कहा कि धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण मार्गों पर अच्छी सड़कें हों। प्रत्येक जिले के सिख, बौद्ध, जैन, वाल्मीकि, रविदासी, कबीरपंथी सहित सभी पंथों व संप्रदायों के धार्मिक, एतिहासिक व पौराणिक महत्व के स्थलों को जोड़ा जाए। मार्ग का चयन मानक के अनुरूप ही हो। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर धर्मार्थ कार्य विभाग और संबंधित जिलाधिकारी के सहयोग से इसे समय से पूरा कराएं।

तीन छोटे पुलों के निर्माण की योजना

योगी ने कहा कि सड़क निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखें। गैर जरूरी ढंग से पेड़ नहीं कटने चाहिए। देवरिया–बरहज मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के प्रस्ताव भी मांगे। औद्योगिक क्षेत्रों तक आने–जाने के लिए चयनित मार्गों को यथासंभव फोर लेन मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए। सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख जिला मार्गों को न्यूनतम दो–लेन (7 मीटर) और अन्य जिला मार्गों को न्यूनतम डेढ़–लेन (5.50 मीटर) चौडाई में निर्माण कराया जाए। हर विधानसभा क्षेत्र में जरूरत के अनुसार 3 लघु सेतुओं के निर्माण की कार्ययोजना तैयार की जाए।

यूपी में गुलाबी ठंड की दस्तक, प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बूंदाबांदी के आसार

लखनऊ, संवाददाता। मौसम का मिजाज धीरे–धीरे ठंड की ओर बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे सुबह और शाम के समय ठंड महसूस होने लगी है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में शुष्क मौसम के कारण तापमान में हल्की गिरावट बनी रह सकती है, जिससे ठंड धीरे–धीरे बढ़ने की संभावना है। यह मौसम किसानों और अन्य कामकाजी लोगों के लिए अनुकूल माना जा सकता है, हालांकि सुबह के समय यात्रा करने वालों को धुंध और कोहरे के कारण सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

वहीं, चार नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जिससे ठंड में मामूली वृद्धि का अनुमान है। अगले सात दिन में राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। आठ नवंबर तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह के समय कई जगहों पर हल्की धुंध और कोहरे का असर रहेगा, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम के साथ–साथ सुबह के समय कहीं–कहीं धुंध और कोहरा छाने की संभावना है। हालांकि चार नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से घने कोहरे की चेतावनी भी दी है। इन दिनों में सतही दृश्यता 50 से 500 मीटर तक गिरने की संभावना है, जिससे परिवहन और यात्रा में बाधा आ सकती है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही तापमान में उतार–चढ़ाव का असर दिखने लगा है। पिछले चार दिन में न्यूनतम तापमान में 20.0 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 15.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जिससे रात में हल्की सर्दी पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम में इस तरह के बदलाव की मुख्य वजह उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा का चलना है। लगातार इस दिशा से हवा चलते रहने से सर्दी का बढ़ना शुरू हो जाएगा। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 15.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

जबकि वातावरण में नमी का अधिकतम प्रतिशत 86 और न्यूनतम प्रतिशत 51 रहा। उत्तर पश्चिमी दिशा से 1.5 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चली। आने वाले दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में सर्दी का बढ़ना शुरू हो जाएगा। किसानों के लिए सलाह है कि वो गेहूं और रबी की फसलों की बोआई शुरू कर सकते हैं।

तारीख बदलने पर सपा-भाजपा के बीच वार-पलटवार

लखनऊ, संवाददाता। विधानसभा उपचुनाव के मतदान की तिथि को एक सप्ताह और बढ़ाने के चुनाव आयोग के निर्णय के बाद सपा और भाजपा के बीच वार–पलटवार शुरू हो गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे।

इस पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव का तिथि परिवर्तन पर दुखी होना ...वाह ! यह वही दुख है जो साइकिल पंचर होने पर होता है।

वहीं, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा के लिए पराजय एक सप्ताह और खिसकी है। सपा के लिए अवसर है कि एक हफ्ते में अपने पराजय का मार्जिन कैसे कम कर सके? भाजपा चुनाव के लिए तैयार है।

भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी– अखिलेश

सपा प्रमुख ने एक्स पर कहा कि पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख, भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। इससे पहले भी सपा प्रमुख ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं कराए जाने पर भी इसी अंदाज में 'जिसने जंग टाली है, समझो उसने जंग हारी है' कहकर तंज कसा था। उन्होंने आगे लिखा कि दरअसल बात ये है कि उत्तर प्रदेश में 'महा–बेरोजगारी' की वजह से जो लोग पूरे देश में काम और रोजगार के लिए जाते हैं, वो दीपावली

और छठ की छुट्टी लेकर आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनावों को आगे खिसका दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाएं। उन्होंने आगे कहा कि ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे।

जनता की भावनाओं का आदर – मौर्य

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि 20 नवंबर तय करके जनता की भावनाओं का आदर किया है। यूपी की जनता ने साइकिल को पंचर कर सैफई के गैराज में भेजने का मन बना लिया है। हर बूथ पर कमल खिलेगा और सपा की बचकानी राजनीति की दुकान बंद होगी।

संक्षिप्त खबरें

उड़ान में 97 हजार विदेशी सिगरेट बरामद

लखनऊ, संवाददाता। बैंकाक से लखनऊ पहुंची थाई एयर एशिया की उड़ान से कस्टम ने तीन यात्रियों के बैग से 97 हजार विदेशी सिगरेट बरामद कीं। इनकी कीमत 16.49 लाख रुपये है। रविवार को थाई एयर एशिया की फ्लाइट बैंकाक से रात 8:23 बजे चलकर अमौसी एयरपोर्ट पर रात 10:23 बजे लैंड हुई। इसके बाद तीन यात्रियों के बैग एक्सरे मशीन से गुजरे तो उनमें संदिग्ध वस्तुएं होने का संदेह हुआ। इसके बाद कस्टम के अधिकारियों ने तीनों यात्रियों के बैग को गहनता से जांचा। इसमें दो के बैग से 30–30 हजार और तीसरे के बैग से 37 हजार सिगरेट मिली।

18 सेवानिवृत्त रेलकर्मियों को मिला समापक भुगतान

लखनऊ, संवाददाता। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के हजरतगंज स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बहुउद्देशीय हाल में सोमवार को सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी सतीश कुमार श्रीवास्तव ने 18 रेलकर्मियों को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी। कर्मचारियों को भुगतान के रूप में समापक राशि व सेवानिवृत्त प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी ने सेवानिवृत्त कर्मियों को रेलवे के प्रति समर्पण, निष्ठा एवं योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। एनई रेलवे मजदूर यूनियन लखनऊ मंडल के मंत्री आरएन गर्ग उपस्थित रहे।

डेंगू के नौ मरीज मिले

लखनऊ, संवाददाता। शहर में सोमवार को डेंगू के नौ मरीज मिले। सीएमओ के प्रवक्ता योगेश ने बताया कि सबसे अधिक पांच केस आलमबाग से मिले। ऐशबाग से दो और रेडक्रॉस व अलीगंज से एक–एक मरीज मिला। टीमों ने 1473 घरों व उनके आस–पास जायजा लिया। छह घरों में मच्छर पनपने की स्थितियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। इस वर्ष जनपद में डेंगू के 2120, मलेरिया के 473 रोगी केस मिल चुके हैं।

इंटरनेट ठप जवाहर भवन में नहीं बने तत्काल टिकट

लखनऊ, संवाददाता। जवाहर भवन के रेल आरक्षण केंद्र का इंटरनेट ठप होने से सोमवार को तत्काल टिकट नहीं बन सके। जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय, महामंत्री राम कुमार धानुक ने कहा, दीपावली के बाद कर्मचारियों के परिजनों की वापसी के तत्काल टिकट नहीं बन सके। इस पर उन्होंने बीएसएनएल विभाग को जिम्मेदार बता अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने भविष्य में ऐसी लापरवाही होने पर आंदोलन चलाने की चेतावनी दी।

काम कराया, मानदेय दिया नहीं और नौकरी से भी निकाल रहे

लखनऊ, संवाददाता। संविदा बिजली कर्मचारियों से अधिकारियों ने काम कराया, मानदेय भी नहीं दिया। अब बिना किसी नोटिस के हटाने की तैयारी कर रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने अफसरों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। इस पर सोमवार को प्रदर्शन करते हुए अधीक्षण अभियंता चौक कार्यालय का घेराव कर दिया। कर्मचारियों ने बताया कि अक्तूबर माह का मानदेय दीपावली से पहले देने का वादा था, लेकिन किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। सोमवार को मानदेय की मांग को लेकर कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि बिना नोटिस के उन्हें हटाया जा रहा है। संविदा कर्मचारी मनोज, अमरेन्द्र, राजू ने कहा कि नौकरी का डर दिखाकर अधिकारी उनका शोषण करते हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वह पिछले 10 सालों में सेवा में हैं। यदि किसी पोल के ऊपर कोई कार्य होता है तो उन्हें ही चढ़ाया जाता है। इस दौरान सुरक्षा के उपकरण तक नहीं दिए जाते हैं। कर्मचारियों ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कहा था कि किसी भी संविदा कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा।

वापसी के लिए उमड़ी रेलयात्रियों की भीड़

लखनऊ, संवाददाता। दीपावली व भैया दूज मनाने के बाद दिल्ली, मुंबई लौटने का सिलसिला तेज हो गया है। छठ के लिए भी लोग पूर्वांचल के जिलों व बिहार को जा रहे हैं। इससे ट्रेनों में भीड़ है। सोमवार रात करीब नौ बजे से ही लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को पकड़ने के लिए यात्रियों की भी चारबाग पहुंचने लगे। इससे पूर्व लखनऊ जंक्शन पर पुष्पक एक्सप्रेस के लिए यात्रियों की भीड़ रही। साढ़े नौ बजे तक चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर गाड़ियों और यात्रियों की भीड़ से जाम जैसी स्थिति बन गई। देर रात चारबाग, आलमबाग, कैसरबाग और अवध कमता बस अड्डे पर भी यात्रियों की भीड़ दिखी। रोडवेज ने पहले से ही अतिरिक्त बसों को बैकअप में रखा हुआ है। रोडवेज बसों और ट्रेनों में जगह नहीं मिलने का फायदा डग्गामार वाहन संचालकों को हो रहा है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।